Amarujala

Uttarakhand cabinet decision on UPNL contract employees

देहरादून स्थित सचिवालय में रविवार देर रात तक चली राज्य कैबिनेट की बैठक में 18 हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को विभागीय संविदा पर रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।

प्राविधिक शिक्षा परिषद की नियमावली बनाने के साथ ही शिक्षा प्रेरकों का मानदेय तीन हजार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। मैराथन चली बैठक में पर्यटन, वन, समाज कल्याण, गृह, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आबकारी समेत तमाम विभागों से जुड़े प्रस्ताव रखे गए। दोपहर तीन बजे शुरू हुई बैठक देर रात 12 बजे समाप्त हुई। बैठक में रखे गए प्रस्तावों में चुनावी वर्ष की झलक साफ दिखाई दी।

आपदा में प्रभावित वाहनों को अगले आठ साल तक रोड टैक्स में 25 फीसदी रियायत का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया गया। इसके अलावा सरकारी खरीद का गेहूं एक रुपये प्रति किलो कम करने, मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के संबंधी नियमावली, वनकर्मियों को दिया जाने वाला धुलाई भत्ता पुलिस के बराबर करने, इको सेंसिटिव जोन में दी गई रियायतों से संबंधी, नगर निगम व्यावसायिक नियमावली संबंधी और एससी-एसटी अवस्थापना विकास योजनाओं संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए।